राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0

सर्जना

01 जुलाई 2025 | अंक: 17

राज्य नगरीय विकास अभिकरण की निदेशक बनीं श्रीमती अपूर्वा दुबे (आईएएस)

श्रीमती अपूर्वा दुबे (आईएएस) ने दिनांक 23 मई 2025 को राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इसके उपरांत निदेशक सूडा ने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ एक परिचयात्मक बैठक की और नगरीय क्षेत्रों के समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। निदेशक सूडा ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप शहरी गरीबों के उत्थान के लिए संचालित होने वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया। श्रीमती अपूर्वा दुबे (आईएएस) का निदेशक सूडा के पद पर स्थानंतरण अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से हुआ है। इससे पूर्व वह जिलाधिकारी फतेहपुर, जिलाधिकारी उन्नाव, सीडीओ फर्रुखाबाद, मुख्य विकास अधिकारी अमेठी व मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पद की जिम्मेदारी कुशलपूर्वक निभा चुकी हैं।

प्रस्तावित सामुदायिक रसोई के संचालन हेतु परामर्श कार्यशाला

प्रदेश में शहरी गरीबों व जरूरतमंदों के लिए पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन किफायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने हेतु सामुदायिक रसोई की स्थापना एवं संचालन हेतु अन्य राज्यों में संचालित रसोईयों के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितग्राहियों के साथ परामर्श कार्यशाला का आयोजन दिनांक 18 जून 2025 को निदेशक सूडा श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में सूडा भवन में हुआ।

उक्त कार्यशाला में निदेशक सूडा द्वारा स्वागत उद्बोधन में प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए साफ स्वच्छ, स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। साथ ही साथ शहरी गरीब व जरूरतमंदों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश में प्रस्तावित सामुदायिक रसोई की स्थापना एवं संचालन के संबंध में चर्चा की गई।

उक्त कार्यशाला में विशेष सचिव, श्री सत्य प्रकाश पटेल, नगरीय विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग उत्तर प्रदेश शासन, श्री सत्य प्रकाश, नगर आयुक्त झांसी, पूर्व नगर आयुक्त लखनऊ, श्री इन्द्रजीत सिंह, विशेष सचिव-निदेशक नेडा उत्तर प्रदेश, उप खाद्य आयुक्त लखनऊ श्री वीपी सिंह द्वारा प्रतिभाग किया गया। साथ ही साथ सूडा के वित्त नियंत्रक श्री संजीव गुप्त, कार्यक्रम अधिकारी श्री अतुल सिंह चौहान, परियोजना अधिकारी डूडा लखनऊ, श्री चंद्र कांत त्रिपाठी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

उड़ीसा राज्य में संचालित आहार योजना के नोडल अधिकारी श्री चित्ता रंजन महोना द्वारा उड़ीसा में संचालित 169 आहार केंद्रों की स्थापना एवं संचालन और सुबह का नाश्ता एवं दोपहर और रात्रि के भोजन के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

मध्य प्रदेश राज्य में संचालित दीनदयाल रसोई योजना के नोडल अधिकारी श्री दुर्गेश तिवारी द्वारा एमपी में 166 स्थायी रसोइयों एवं 25 चलित फूड वैनों की स्थापना एवं संचालन एवं दोपहर के भोजन के सबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

सामुदायिक रसोई के संचालन हेतु अन्य हितग्राहियों जैसे आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन के संचालक हरे कृष्ण मिशन के प्रतिनिधि श्री सुरेश गौड़ द्वारा आन्ध्र प्रदेश में स्थापित 15 एकीकृत रसोई एवं 203 कैंटीन जहां पर भोजन वितरण किया जाता है, के साथ-साथ सुबह का नाश्ता एवं दोपहर और रात्रि के भोजन के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

अक्षय पात्र लखनऊ के प्रतिनिधि श्री विक्रांत मोहन द्वारा सरकारी स्कूलों में वितरित किए जाने वाले मिड डे मील एवं स्थापित केंद्रीयकृत रसोई संचालन के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।
गैलेंट गोरखपुर के प्रतिनिधि श्री बृज मोहन जोशी द्वारा गोरखपुर में दो फूड वैनों के माध्यम से पांच अस्पतालों में जरूरतमंदों को उपलब्ध कराए जा रहे भोजन एवं स्थापित केंद्रीयकृत रसोई के संबंध में प्रस्तुतीकरण के द्वारा अवगत कराया गया।

इसके साथ-साथ मधुरिमा रेस्टोरेंट, अमृत फूड लखनऊ, प्रदीप एआर कैटर्र, बीकानेर वाला लखनऊ, होटल राजस्थान लखनऊ, स्नो फाउनण्टेन आर्टिटेक्ट एवं कंसल्टेंट्स, बीओएच कॉमर्शियल किचन स्पेशलिस्ट के साथ-साथ आईआरसीटीसी की टीम के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उक्त कार्यशाला में आए सामुदायिक रसोई संचालित राज्यों के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितग्राहियों से प्रदेश में प्रस्तावित सामुदायिक रसोई की स्थापना एवं संचालन के संबंध में विचार-विमर्श एंव सुझाव लिए गए।

निदेशक सूडा ने किया जनपद हरदोई में कान्हा गौशाला, एमआरएफ सेंटर आदि का निरीक्षण

शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में दिनांक 6 जून 2025 को निदेशक सूडा, श्रीमती अपूर्वा दुबे ने जनपद हरदोई की कान्हा गौशाला एवं एमआरएफ सेंटर, नगर पालिका परिषद साण्डी का निरीक्षण किया। उक्त निरीक्षण कार्यक्रम में निदेशक सूडा ने कान्हा गौशाल की साफ-सफाई व गायों को मिलने वाले चारे व चिकित्सा सुविधाओं की हकीकत को परखा। इसके साथ ही एमआरएफ सेंटर के निरीक्षण के दौरान निदेशक सूडा ने कूड़ा प्रबंधन एवं कचरा निस्तारण के उपयोग में आने वाली मशीनों का जायजा लिया तथा सेंटर के स्टाफ से संवाद भी किया। इसके बाद निदेशक सूडा ने शहीद उद्यान, नगर पालिका हरदोई में पौधारोपण किया। निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत निदेशक सूडा ने कम्पोस्ट पिट, नगर पालिका कैम्पस हरदोई तथा लोक निर्माण भवन का भी निरीक्षण किया। उक्त कार्यक्रम में निदेशक सूडा ने लोक निर्माण भवन में समस्त अधिशासी अधिकारियों के साथ आने वाले पर्वों एवं योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की।

69 लाभार्थियों को मिली उनके सपनों के घर की चाबी

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों के लिए 19 जून 2025 का दिन यादगार बन गया है। राजधानी लखनऊ की अवध विहार योजना में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 69 लाभार्थियों को समस्त अभिलेखों की पूर्ति के पश्चात उनके आवास का कब्जा मिल गया। इस अवसर पर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी एलएचपी के लाभार्थियों की रजिस्ट्री के साथ ही अन्य अभिलेखीय कार्य पूर्ण होने के साथ ही लाभार्थियों को उनके आवासों का कब्जा भी दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज 69 लोगों को उनके सपनों के घर में प्रवेश मिल गया।

योजना की लाभार्थी श्रीमती रोली दीक्षित कहतीं हैं कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे आज के दिन ऐसा उपहार मिला है जिसे मैं इस जिंदगी में नहीं भूल सकती। इसी प्रकार योजना से आच्छादित श्री रमेश कुमार सिंह, कहते हैं कि आज मुझे सिर्फ घर ही नहीं मिला है बल्कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सहयोग से अपने जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली है। सही मायनों में तो आज मेरा जीवन रोशनी से भर उठा है। योजना के एक अन्य लाभार्थी श्री यश कुमार कहते हैं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त योजना में आवास पाकर मैं अपने आपको धन्य मान रहा हूं। मैं इस बात को लेकर खुश रोमांचित हूं कि दुनिया की बेहतरीन तकनीक से मेरे सपनों का घर बन गया है। आपको बता दें कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 1,040 परिवारों को उनके सपनों का घर देने का काम किया है।

उक्त अवसर पर निदेशक सूडा श्री अपूर्वा दुबे ने बताया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया है। उक्त योजना में 1,040 आवास बनाए गए हैं। इन आवासों के निर्माण में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया है। ये मकान आपदारोधी व पर्यावरण के अनुकूल हैं। देश में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉमवर्क तकनीकी का प्रयोग लखनऊ सहित देश के छह अन्य शहरों में किया गया है। लखनऊ में बना लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रदेश ही नहीं देश के निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि समस्त अभिलेखीय कार्यवाही पूर्ण होने के साथ-साथ लाभार्थियों को उनके आवासों का कब्जा दिया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य यह है कि जल्द से जल्द समस्त लाभार्थियों को उनके आवासों का कब्जा दिया जा सके। इसके लिए मिशन मोड में काम किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू 2.0 की तीसरी सीएसएमसी बैठक में 73,594 आवासों की मिली स्वीकृति

दिनांक 18 जून 2025 को सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, श्री कतिकीथला श्रीनिवास की अध्यक्षता में पीएमएवाई-यू की 73वीं एवं पीएमएवाई-यू 2.0 की तीसरी सीएसएमसी बैठक वर्चुअल माध्यम से हुई। उक्त बैठक में 73,594 आवासों की स्वीकृति मिली। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में निदेशक सूडा, श्रीमती अपूर्वा दुबे, कार्यक्रम अधिकारी सूडा, श्री अतुल सिंह चौहान ने प्रतिभाग किया।

अनुश्रवण समिति की बैठक

दिनांक 7 मई 2025 को सूडा मुख्यालय में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष श्री बलविन्दर सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में सहायक निदेशक सूडा, श्रीमती मोनिका वर्मा, वित्त नियंत्रक सूडा, श्री संजीव गुप्ता तथा मुख्यालय के अन्य अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। अनुश्रवण समिति की बैठक में राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा प्रदेश के समस्त जनपदों में योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु चर्चा भी की गई।

जल परीक्षण का कार्य मानव सेवा जैसा: आरती सिंह

अमृत मित्र योजना एक ओर जहां हर घर शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने का काम कर रही है तो वहीं दूसरी ओर योजना के माध्यम से महिलाएं समाज में अलग पहचान स्थापित करने के साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर भी बन रहीं हैं। जनपद गोरखपुर की निवासी श्रीमती आरती सिंह अमृत मित्र योजना के अंतर्गत जल परीक्षण का कार्य करती हैं। श्रीमती आरती सिंह बताती हैं कि हर घर शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए जल परीक्षण का काम मेरे लिए मानव सेवा से कम नहीं है। आज मैं घर-घर जाकर जल की शुद्धता का परीक्षण करती हूं। इस काम ने मुझे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही समाज में मुझे सशक्त व स्वावलम्बी महिला के रूप में पहचान भी दी है।

स्वयं सहायता समूह ने बदली मेरी जिंदगी: सुमन गुप्ता

स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये समूह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सफल साबित हो रहे हैं। एसएचजी से जुड़कर महिलाएं अपना व्यवसाय या अन्य आर्थिक गतिविधियों को शुरू कर सकती हैं। महिलाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करती हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है।

जनपद रायबरेली निवासी श्रीमती सुमन गुप्ता बताती हैं कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर काम करने का अनुभव मेरे लिए अभूतपूर्व साबित हुआ है। पहले मैं छोटी सी दुकान में दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को मेरे पास लाभ के नाम पर मुश्किल से सौ से दो सौ रुपए ही होते थे। ऐसे में परिवार का भरण-पोषण ही मेरे लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन जब से मैं डूडा के माध्यम से स्वयं सहायता समूह का हिस्सा बनी मेरी जिंदगी ही बदल गई। हम समूह की महिलाएं पापड़, चिप्स आदि बनाती हैं और अच्छे दामों पर हमारे उत्पादों की बिक्री भी होती है। जिससे मेरी भी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी हुई है। रिवॉल्विंग फंड तथा सीसीएल के माध्यम से हमें अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायता मिली है।

कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता .....

कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारों....हिन्दी के महान कवि दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियां जनपद मथुरा निवासी श्रीमती सोनिया माथुर पर सटीक बैठती हैं।

श्रीमती सोनिया माथुरा में किराए के एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी काट रहीं थीं। पति की आमदनी भी कुछ खास नहीं थी, बस किसी तरह परिवार चल रहा था। एक दिन उनकी जिंदगी का यह सहारा भी उनसे छिन गया। पति की मृत्यु के बाद सोनिया के लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी चुनौती भरा हो गया। रोजी-रोजगार का कोई साधन नहीं था। इस बुरे वक्त में अपनों ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। सोनिया पूरी तरह से हताश हो चुकी थीं।
इसी बीच उनको डूडा के द्वारा लगाए कैम्प के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के विषय में जानकारी मिली। सोनिया ने स्थानीय डूडा कार्यालय में जाकर आवेदन किया। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सोनिया पीएमएवाई-यू की लाभार्थी बन गईं और तीन किस्तों में मिले ढाई लाख रुपए से उन्होंने अपना पक्का घर बनवाया है। दरअसल सोनिया व उनके पति ने छोटी-छोटी बचत करके किसी तरह जमीन का एक टुकडा खरीदा था। आज अपने पति की इसी निशानी पर उनका घर निर्मित है।

अपना घर होने से सोनिया को काफी हौसला मिला। अब सोनिया समाज को दिखाना चाहती थीं कि अकेली औरत भी सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। इसके बाद स्वयं सहायता समूह का गठन किया। इसके बाद शहरी क्षेत्र में संचालित सभी प्राइमरी स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण का काम उनके समूह को मिल गया। जिससे उनको अच्छा लाभ मिला।

इसके बाद उनको एक सरकारी विद्यालय में कैंटीन संचालन का कार्य भी नगर निगम द्वारा मिल गया, जिसे वो आज भी संचालित कर रहीं हैं। ये तो बस सोनिया के सफलता के सफर की शुरुआत थी।
नगर निगम द्वारा सोनिया की एसएचजी को सार्वजनिक शौचालय के संचालन का कार्य भी मिल गया। जिससे उनकी व समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हुई। सोनिया ने इसके बाद अपना बुटीक भी खोला है और आज ओडीओपी के अंतर्गत लड्डू गोपाल पोशाक केंद्र का संचालन भी कर रहीं हैं। आज श्रीमती सोनिया माथुर किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। वो महिला सशक्तिकरण, स्वावलंबन का प्रकाश स्तम्भ बन गई है। जिनसे प्रेरणा पाकर आज कई महिलाएं सफलता की नई कहानियां लिख रहीं हैं।

DAY-NULM UTTAR PRADESH
@nulmup

जनपद मऊ निवासी श्रीमती बिन्दु मौर्या पीएम स्वनिधि योजना से आच्छादित होकर अपने परिवार का सहारा बनी हैं।

तो जानिए उनकी जुबानी उनके अनुभव की कहानी।

#DAYNULM #UPSUDA #EmpoweringIndia #PMSVANidhi #StreetVendor

Translate post

Pradhan Mantri Awas Y... Promote
@PMAYU_UP

आज दिनांक 30 मई 2025 को निदेशक सूडा, श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में सूडा मुख्यालय में 07 जनपदो क्रमशः बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मेरठ, बिजनौर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मिर्जापुर की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के प्रगति की समीक्षा की गई।

Translate post

pmayu_up and suda.uttarpradesh
24 June

26 1

pmayu_up प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी महिला सशक्तिकरण का आधार बनी है।

योजना के माध्यम से मिले पक्के आवासों का मालिकाना हक महिलाओं को मिलने से समाज में न सिर्फ उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई है बल्कि उनको नई पहचान भी मिली है।

@aksharmabharat @principalsecy_udd @mohua_india @pmay_urban @nagarvikas_up @mygovindia @mygovup @suda.uttarpradesh

Pradhan Mantri Awas Y... Promote
@PMAYU_UP

10 साल बेमिसाल!

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ने प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों को उनके सपनों का घर देने का काम सफलतापूर्वक किया है। सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के घरों के रूप में न सिर्फ सपनों ने मूर्त रूप धारण किया है बल्कि सुरक्षित भविष्य की बुनियाद भी बन रहे हैं।

Translate post

हिन्दुस्तान
भरोसा नए हिन्दुस्तान का

लाभार्थियों को मिले 69 पीएम आवास

लखनऊ, विसं। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों के लिए गुरुवार का दिन यादगार बन गया है। लखनऊ की अवध विहार योजना में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 69 लाभार्थियों को समस्त अभिलेखों की पूर्ति के बाद गुरुवार को आवास का कब्जा मिल गया। कब्जा पाने वाले लाभार्थियों के चेहरे खुशी से दमक उठे।

पीएमएवाई-यू के अंतर्गत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभार्थी को चाबी सौंपी गई।

योजना की लाभार्थी रोली दीक्षित कहती हैं कि मुझे आज के दिन ऐसा उपहार मिला है, जिसे मैं इस जिंदगी में नहीं भूल सकती। योजना के एक अन्य लाभार्थी यश कुमार कहते हैं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त योजना में आवास पाकर मैं खुद को धन्य मान रहा हूं। निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने बताया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया है। इस योजना में 1,040 आवास बनाए गए हैं। इन आवासों के निर्माण में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग किया है। ये मकान आपदारोधी व पर्यावरण के अनुकूल हैं। देश में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉमवर्क तकनीकी का प्रयोग लखनऊ सहित देश के छह अन्य शहरों में किया गया है। लखनऊ में बना लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रदेश ही नहीं देश के निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।

www.facebook.com/rashtriyasahara https://twitter.com/SaharaRashtriya www.rashtriyasahara.com
राष्ट्रीय सहारा
लखनऊ

69 लाभार्थियों को मिली उनके सपनों के घर की चाबी

लखनऊ (एसएनबी)। अवध विहार योजना में पीएमएवाई शहरी के अंतर्गत बने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के 69 लाभार्थियों को उनके आवास का कब्जा मिल गया। लाभार्थियों के चेहरे खुशी से दमक उठे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी एलएचपी के लाभार्थियों की रजिस्ट्री के साथ ही अन्य अभिलेखीय कार्य पूर्ण होने के साथ ही आवासों का कब्जा भी दिया जा रहा है। आज 69 लोगों को उनके सपनों के घर में प्रवेश मिल गया। योजना की लाभार्थी रोली दीक्षित कहती हैं कि आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे आज के दिन ऐसा उपहार मिला है जिसे मैं इस जिंदगी में नहीं भूल सकती। रमेश कुमार सिंह कहते हैं कि मुझे सिर्फ घर ही नहीं मिला है बल्कि मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के सहयोग से अपने जीवन की एक बहुत बड़ी चुनौती पर विजय प्राप्त कर ली है।

पीएम आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों के खिले चेहरे

योजना के एक अन्य लाभार्थी यश कुमार कहते हैं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त योजना में आवास पाकर मैं अपने आपको धन्य मान रहा हूं। मैं इसे बात को लेकर खुश रोमांचित हूं कि दुनिया की बेहतरीन तकनीकी से मेरे सपनों का घर बनाया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 1,040 परिवारों को उनके सपनों का घर देने का काम किया है। निदेशक सूडा अपूर्वा दुबे ने बताया कि राज्य नगरीय विकास अभिकरण सूडा की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट का निर्माण कराया गया है। योजना में 1,040 आवास बनाए गए हैं। ये मकान आपदारोधी व पर्यावरण के अनुकूल हैं। देश में पीवीसी स्टे इन प्लेस फॉमवर्क तकनीकी का प्रयोग लखनऊ सहित देश के छह अन्य शहरों में किया गया है। लखनऊ में बना लाइट हाउस प्रोजेक्ट प्रदेश ही नहीं देश के निर्माण क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेन्ज-इण्डिया के अन्तर्गत लाइट हाउस प्रोजेक्ट अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर-5 में बनाए गए है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में 34.50 वर्गमी. कारपेट एरिया के कुल 1040 भवन सम्मिलित है, जो सिटल्ट प्लस 13 प्रकार के चार बहुमंजिला ब्लाकों में निर्मित है। उक्त परियोजना में आवास के साथ-साथ कम्यूनिटी सेन्टर, कॉमर्शियल सेन्टर, सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एसटीपी), पेयजल, ड्रेनेज, आन्तरिक सडकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर लाईट, खुले खेल क्षेत्र, पार्किंग इत्यादि सुविधाएँ भी लाभार्थियों को मिलेंगी। परियोजना की कुल निर्माण लागत 130.90 करोड़ रुपए है, जिसमें समस्त अवस्थापना सहित प्रति आवास लागत 12.59 लाख रुपए है। परियोजना में कुल 7.83 लाख रुपये प्रति आवास का शासकीय अनुदान दिया गया है। अवशेष धनराशि 5.26 लाख रुपये लाभार्थी को देना है।

अमर उजाला
लखनऊ

प्रेरणा | जेम पोर्टल पर खरीद में उत्तर प्रदेश ने बनाया कीर्तिमान...8 | उत्तर प्रदेश

पहले चरण में 17 शहरों में खुलेंगी सामुदायिक रसोई

लखनऊ। प्रदेश के शहरों में गरीबों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित सामुदायिक रसोई के संचालन की कवायद शुरू हो गई है। बुधवार को राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) की निदेशक अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इसमें उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ऐसी रसोई के संचालकों समेत यूपी के भी होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने प्रस्तुतिकरण दिया। तय हुआ है कि पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नगर निगम वाले 17 शहरों में सामुदायिक रसोई खोली जाएंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से छोटे शहरों में भी इसका विस्तार किया जाएगा।

सूडा निदेशालय के सभागार में आयोजित कार्यशाला में शहरी गरीबों व जरूरतमंदों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन किफायती दरों पर उपलब्ध कराने पर चर्चा हुई। इसके लिए सामुदायिक रसोई के स्थापना एवं संचालन के लिए अन्य राज्यों में संचालित रसोइयों के प्रतिनिधियों एवं अन्य हितग्राहियों के साथ परामर्श किया गया। आंध्र प्रदेश में अन्ना कैंटीन के संचालक और लखनऊ में अक्षय पात्र के प्रतिनिधि विक्रांत मोहन ने भी प्रस्तुतीकरण दिया। ब्यूरो

सूडा निदेशक ने कार्यशाला में कई प्रदेशों के फूड वेंडरों से की चर्चा

सूडा निदेशक अपूर्वा दुबे

दैनिक जागरण

गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराएगी सामुदायिक रसोई

राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: शहरी गरीबों व जरूरतमंदों के लिए किफायती दरों पर पौष्टिक व स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक रसोई की स्थापना की कसरत तेज होने जा रही है। बुधवार को सूडा भवन में आयोजित परामर्श कार्यशाला में अन्य राज्यों में संचालित रसोई के प्रतिनिधियों व अन्य हितधारकों ने अपने-अपने प्रस्तुतिकरण दिए। सूडा निदेशक अपूर्वा दुबे ने कहा कि जल्द ही कार्ययोजना तैयार कर प्रदेश में सामुदायिक रसोई की स्थापना की कार्रवाई शुरू होगी।

कार्यशाला में सूडा निदेशक ने गरीबों के लिए स्वच्छ, स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रस्तावित सामुदायिक रसोई योजना की जानकारी दी। ओडिशा में आहार योजना के नोडल अधिकारी चित्ता रंजन महोना ने 169 आहार केंद्रों की स्थापना, संचालन और सुबह का नाश्ता, दोपहर और रात्रि के भोजन के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के नोडल अधिकारी दुर्गेश तिवारी ने वहां 166 स्थायी रसोई व 25 चलित फूड वैनों के संचालन की जानकारी दी।